



2026:AHC-LKO:42260-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5231 वर्ष 2026

जुबेर उर्फ जुबेर अहमद याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह , लखनऊ

एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार शुक्ला, गर्जेन्द्र प्रताप, प्रमोद
कुमार शुक्ला, सुरेश कुमार पांडे
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

माननीय न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत विरोधी पक्षकार संख्या 4 को सूचना दिया जाना अपवर्जित किया जाता है।
3. याचिका पुलिस थाना-टिकैत नगर, जनपद-बाराबंकी में बी० एन० एस० की धाराओं 131, 351(3) और 352 तथा उ० प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(3) के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 0124 वर्ष 2026 में पंजीकृत प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.05.2026 को उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करते हुए निरस्त किए जाने की मांग करती है।
4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कथित रूप से किए गए अपराधों में सात वर्ष तक के कारावास का दंड अंतर्विष्ट है। ऐसी परिस्थितियों में विवेचना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और धारा 41-क (तत्स्थानी धारा 35 बीएनएसएस) के उपबंधों का अनुपालन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** में प्रतिपादित अनुसार किया जाए।
5. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष पर विचार किया । **अर्नेश कुमार** (उपरोक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक भाग) निर्णीत किया गया है:-

"9. एक अन्य प्रावधान अर्थात् धारा 41क दं०प्र०सं० जिसका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी या अभियुक्त पर मंडरा रही गिरफ्तारी की धमकी से बचना है को प्रभावी किया जाना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम 5 वर्ष 2009) की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 41क जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है
निम्नानुसार है:

"41क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना-

(1) पुलिस अधिकारी सभी मामलों में जहां धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त शिकायत की गई है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष या सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना की शर्तों का अनुपालन करे।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है वहां पुलिस अधिकारी इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है।"

"उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि सभी मामलों में जहां दं० प्र० सं० की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को किसी विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करना अपेक्षित है। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करती है और यह आगे अधिदेशित करती है कि यदि ऐसा अभियुक्त सूचना की शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी दं० प्र० सं० की धारा 41 के अंतर्गत परिकल्पित गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्त का अनुपालन किया जाना है और वह उपरोक्तानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा उसी संवीक्षा के अधीन होगी।"(हमारे द्वारा प्रभाव वर्धित)

6. अर्नेश कुमार मामले (उपरोक्त) में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए पक्ष पर विचार करते हुए, जिसका प्रासंगिक भाग ऊपर उद्धृत किया गया है, यह याचिका दंड प्रक्रिया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता की धारा 41-क (तत्स्थानी धारा 35 बीएनएसएस) के उपबंधों और अर्नेश कुमार मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद) (न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

29 जून, 2026

फहीम/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।